भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3289

उत्तर देने की तारीख : 12.03.2026

एमएसएमई का विकास

3289. श्री गणेश सिंह :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अवसंरचना के विकास और क्लस्टर-आधारित विकास में तेजी लाने के लिए परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि योजना (स्फूर्ति), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक दर्ज की गई प्रमुख पहलों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार एमएसएमई की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण, उद्योग 4.0 के अंगीकरण, एआई/आईओटी-आधारित समाधान, ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग और प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा दे रही है और इस दिशा में किए गए ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार स्थानीय रोजगार, नवाचार और निर्यात क्षमता को और मजबूत करने के लिए उभरते हुए औद्योगिक जिलों, विशेषकर मध्य प्रदेश के सतना जिले में क्लस्टर-आधारित डिजिटल एमएसएमई हब या पायलट परियोजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) ने मौजूदा क्लस्टर में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित किए हैं और बुनियादी ढांचागत सुविधाएं (आईडी परियोजनाएं) बनाई / उन्नत की हैं। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 606 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 242 परियोजनाएं चालू हैं और 364 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि (स्फूर्ति) स्कीम के तहत, क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देने, पारंपरिक उद्योगों को सुदृढ़ करने और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। वर्ष 2015-16 से देश भर में कुल 513 क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है, जिसमें भारत सरकार की 1,332.95 करोड़ रुपए की स्वीकृत प्रतिबद्ध सहायता शामिल है। इन क्लस्टरों से हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि प्रसंस्करण, कॅयर, शहद और संबंधित गतिविधियों जैसे विविध क्षेत्रों से जुड़े लगभग 3.03 लाख पारंपरिक कारीगरों को लाभ मिलने का प्रस्ताव है। स्वीकृत कुल क्लस्टरों में से, 378 क्लस्टर वर्तमान में कार्यरत हैं, जबकि आज की तारीख तक 135 क्लस्टर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जो जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल वृद्धि, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार संबंधों में योगदान दे रहे हैं।

सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के तहत, सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए स्वीकार्य घटकों/क्षेत्रों में अन्य के अलावा शामिल हैं:

i. उद्योग 4.0 और इसकी सीखने की सुविधाएं, योज्य विनिर्माण सुविधाएं, डिजिटल अवसंरचना।

ii. डिजाइन/इंक्यूबेशन केंद्र।

iii. प्रशिक्षण केंद्र / कौशल उन्नयन सुविधाएं।

iv. अनुसंधान और विकास केंद्र।

v. सामान्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (सौर, पवन, बायो) और ऊर्जा प्रबंधन उपकरण।

vi. एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास हेतु ग्रीनफील्ड समूहों के लिए सीएफसी ।

एमएसई-सीडीपी एक मांग आधारित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें राज्य सरकारें अपने राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा क्लस्टर की सामान्य जरूरतों के अनुरूप प्रस्ताव भेजती हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले के लिए एमएसई-सीडीपी के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है:

क्र.सं.	**परियोजनाओं का नाम**	**कुल परियोजना लागत**	**भारत सरकार अनुमोदित**	**स्थिति (जारी/पूरा)**
		(लाख रुपए में)		
1	मतेहाना में औद्योगिक क्षेत्र का उन्नयन	1074.39	595.7	जारी
2	नदंतोला, जिला में नया औद्योगिक क्षेत्र।	502.96	201.19	पूरा

देश के औद्योगिक परिदृश्य ने हाल के वर्षों में मूल्य सृजन और प्रतिस्पर्धात्मकता में एमएसएमई के लिए बढ़ी हुई परिचालन दक्षता के साथ डिजिटलीकरण में वृद्धि देखी गई है। डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स लेनदेन, आईओटी सक्षम उत्पादन टूल्स और बेहतर व्यावसायिक संचालन के लिए एआई आधारित प्रौद्योगिकियों में भागीदारी बढ़ी है। एमएसएमई के बीच अधिक उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा के लिए डिजिटल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कई पहलें की हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिलॉकर और इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिनका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर एमएसएमई को लचीला, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाना है, और दूरसंचार विभाग के भारतनेट और पीएम-वाणी जैसे नेटवर्क शामिल हैं, जो किफायती पहुंच और अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के डिजिटल पंजीकरण के माध्यम से उद्यम, प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए टूल रूम / प्रौद्योगिकी केंद्रों में प्रशिक्षण, एमएसएमई इनोवेटिव योजना के माध्यम से नए विचारों और प्रौद्योगिकियों के इन्क्यूबेशन और हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एमएमई परिवर्तन के लिए हरित निवेश और वित्तपोषण स्कीम के माध्यम से एमएसएमई के डिजिटल सशक्तिकरण का समर्थन कर रहा है। वित्तीय प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण और जागरूकता के घटकों को उपर्युक्त सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के डिजाइन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

मंत्रालय ने व्यापार सक्षमता और विपणन (टीम) योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य विक्रेता नेटवर्क प्रतिभागियों (एसएनपी) को ऑनबोर्डिंग, सूचीकरण, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग सामग्री और डिजाइन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के लिए ओपन नेटवर्क पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को शामिल करना है। विशेष रूप से, इन लाभार्थी एमएसएमई में से आधे महिला स्वामित्व वाले उद्यम होंगे।

****